

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 39/2021

चेतराम पुत्र जयपाल जाति जाट, निवासी कुहाड़वास, तहसील बुहाना, जिला झुझुनू।

— अपीलान्त—

—बनाम—

सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना, जिला झुझुनू।

—रेस्पोजेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना  
उनवानी सरकार बनाम चेताराम अंधारा 91 एल.आर.एक्ट 1956  
मुकदमा नम्बर 01/2021 निर्णय दिनांक 25.02.2021

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता -----अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ----- रेस्पोजेन्ट की ओर से।

— निर्णय —

दिनांक 12.01.2023

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम चेताराम मुकदमा नम्बर 01/2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार बुहाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं — कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड-1 में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्त द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्त के खिलाफ बेदखली के आलौच्य आदेश दिनांक 25.02.2021 को पारित किये गये हैं। अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्त ने



जगदीश प्रसाद गौड़  
अति. जिला कलेक्टर  
झुझुनू

दिनांक 11.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जिसमें विवादित भूमि का अपने पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत एवं जल कनेक्शन के बिल प्रस्तुत किये। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 में अपीलान्त द्वारा पेश जबाब नोटिस बाबत कोई विवरण दर्ज नहीं किया। अपीलान्त के विरुद्ध मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में किसी सद्भाविक व्यक्ति को सरसरी प्रोसेडिंग द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है जहां सद्भाविक व कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में रेगुलर कार्यवाही के द्वारा बाद शपथपूर्वक साक्ष्य ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विवादित जमीन पर काफी लोग 50-60 वर्षों से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। उक्त भूमि पर आबाद व्यक्तियों को सरकारी महकमा विद्युत विभाग व जलदाय विभाग ने विद्युत एवं जल कनेक्शन दिये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत पेश जबाब पर ध्यान दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्त का काफी पुराना कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बजंड-1 में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्त द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलान्त के खिलाफ बेदखली के आलौच्य आदेश दिनांक 25.02.2021 को पारित किये गये हैं। अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होने

17  
अति. जिला कलेक्टर  
झुंझुनू

पर अपीलान्त ने दिनांक 11.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जिसमें विवादित भूमि का अपने पुराने कब्जे के संबंध में विद्युत एवं जल कनेक्शन के बिल प्रस्तुत किये। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 में अपीलान्त द्वारा पेश जबाब नोटिस बाबत कोई विवरण दर्ज नहीं किया। अपीलान्त के विरुद्ध मौजूदा प्रकरण में धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। जहां सद्भाविक कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में किसी सद्भाविक व्यक्ति को सरसरी प्रोसेडिंग द्वारा बेदखल नहीं किया जा सकता है जहां सद्भाविक व कब्जे व किस्म जमीन का विवाद हो उस प्रकरण में रेगुलर कार्यवाही के द्वारा बाद शपथपूर्वक साक्ष्य ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विवादित जमीन पर काफी लोग 50-60 वर्षों से रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। उक्त भूमि पर आबाद व्यक्तियों को सरकारी महकमा विद्युत विभाग व जलदाय विभाग ने विद्युत एवं जल कनेक्शन दिये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत पेश जबाब पर ध्यान दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्त का काफी पुराना कब्जा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्त ने ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 373 कुल रकबा 2.65 हैक्टर किस्म बंजड़-1 भूमि में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्त ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्त को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय तथा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे विवादित भूमि पर अपीलान्त का

अति. जिला कलेक्टर  
भुवनेश्वर

कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 उनवानी सरकार बनाम चेताराम मुकदमा नम्बर 01/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।



(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू